अब बाजार ही नियंत्रित करेगा रुपए की चाल

डॉलर बनाम रुपया- सरकार ने दिया फ्री-फ्लोट का संकेत

नई दिल्ली, 07 दिसंबर. भारत की आर्थिक बहसों में लगातार चर्चा का विषय बने भारतीय रुपये को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बेहद स्पष्ट और निर्णायक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि रुपया अब पूरी तरह से बाजार की ताकतों के आधार पर अपना रास्ता खुद चुनेगा. किसी कृत्रिम नियंत्रण, बैंड या तय सीमा को लागू करने का सवाल नहीं है. बाजार ही बता देगा कि भारतीय मुद्रा किस स्तर पर टिकेगी और किस दिशा में आगे बढ़ेगी.

दिल्ली में आयोजित एक समिट में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि रुपये के उतार-चढ़ाव को केवल राजनीतिक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने माना कि अतीत में विपक्ष में रहते हुए उनकी पार्टी ने रुपये की कमजोरी पर सवाल उठाए थे, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि उस समय आर्थिक स्थितियां बिल्कुल भिन्न थीं—महंगाई ऊंचाई पर थी, अर्थव्यवस्था कमजोर थी और फंडामेंटल्स डगमगाए हुए थे.

इसके विपरीत आज भारत मजबूत आर्थिक आधार, स्थिर फंडामेंटल्स और सुदृढ़ नीतिगत ढांचे के साथ खड़ा है. इसी वजह से रुपये की हरकत के बजाय के संदर्भ में समझा जाना चाहिए. इस बीच आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी दोहराया कि केंद्रीय बैंक किसी भी प्राइस-बैंड को लक्षित नहीं करता और विदेशी मुद्रा बाजार को स्वतंत्र रूप से काम करने देता है.

सीतारमण के इस बयान ने कई महीनों से चल रही उस बहस को नया आयाम दे दिया, जिसमें विपक्ष रुपये के उतार-चढ़ाव को लेकर लगातार सवाल उठा रहा था. जब वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या भारतीय मुद्रा इस समय डॉलर के मुकाबले ओवरवैल्यूड है, तो उन्होंने दृढ़ता से कहा कि रुपया अपना स्तर खुद तय करेगा. इस उत्तर के साथ उन्होंने साफ कर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा अब हस्तक्षेप-आधारित नहीं बल्कि बाजार-आधारित है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विपक्ष के दौर में उनकी पार्टी ने रुपये की गिरावट को लेकर सवाल जरूर उठाए थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय स्थितियां अलग थीं. शासनकाल के दौरान महंगाई चरम पर थी, विकास दर ठहरी हुई थी और अर्थव्यवस्था लगातार दबाव झेल रही थी. ऐसे माहौल में मुद्रा की कमजोरी आर्थिक अस्थिरता की सीधी निशानी मानी जाती थी.

भारत का फॉरेक्स दो सप्ताह फिसला, गोल्ड ने बचाई साख

नई दिल्ली, 7 दिसंबर. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई है, जिससे देश के फॉरेक्स पोज़ीशन को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, 28 नवंबर को समाप्त सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 1.88 अरब डॉलर घटकर 686 अरब डॉलर रह गया है. इससे पहले 21 नवंबर वाले सप्ताह में भी इसमें 4.4 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज हुई थी, जिसके बाद कुल भंडार 688 अरब डॉलर पर आ गया था. इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण विदेशी मुद्रा संपत्तियों में आई भारी कमी है. एफसीएस जो भारत के कुल फॉरेक्स में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, उसमें 3.5 अरब डॉलर की कमी आई है.

लावारिस राशि हकदारों को दिलाने का प्रयास

देश के बैंकों में नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपए बिना दावे के पड़ा

बीमा कंपनियों के पास 14,000 करोड़ रुपए

नई दिल्ली, 07 दिसंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार बैंकों और बीमा कंपनियों के पास बिना दावे के लंबे समय से पड़ी हजारों करोड़ रुपये की राशि को उनके असली हकदारों तक अभियान चाल कर पहुंचाना चाहती है क्योंकि यह उनकी सरकार के लिए विश्वास का विषय है.

पीएम मोदी ने यहां एक मीडिया प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में इस बारे में कहा, आज देश के बैंकों में हमारे नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपये बिना दावे के पड़ा है. हमें नहीं पता कि यह पैसा किसका है, यह यूं ही पड़ा है. बीमा कंपनियों के पास 14,000 करोड़ रुपये हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास 3,000 करोड़ रुपये हैं. लाभांश में 9,000 करोड़ रुपये पड़े हैं. यह सारा पैसा बिना दावे के पड़ा है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैसा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का है और सरकार यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह पैसा किसका है, क्योंकि हम इस पैसे के असली मालिक का पता लगाना चाहते हैं. उन्होंने कहा, हमारी सरकार देश में इस धन को इसके मालिकों तक वापस पहुंचाने का प्रयास कर रही है. अब तक, इस पैसे के मालिकों की पहचान के लिए लगभग 500 जिलों में विशेष शिविर लगाये जा चुके हैं और हमने उन्हें कई हजार करोड़ रुपये वापस किये हैं. यह केवल संपत्ति की वापसी की बात नहीं है, यह विश्वास की बात है.

पतंजलि योगपीठ का रूस की सरकार से करार

आरोग्य और आयुर्वेद पर फोकस

नयी दिल्ली, 07 दिसम्बर. पतंजलि समूह ने रूस की सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है जो स्वास्थ्य तथा आरोग्य के संवर्धन, स्वास्थ्य पर्यटन, कुशल मानव संसाधन के आदान-प्रदान तथा अनुसंधान आदि विषयों पर केंद्रित है.

पतंजलि समूह की ओर से योग गुरू स्वामी रामदेव और रूस की सरकार की तरफ से भारत-रूस व्यापार परिषद के अध्यक्ष एवं रूस के वाणिज्य मंत्री सर्गेई चेरेमिन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये. स्वामी रामदेव ने कहा कि रूस में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को लोग पसंद करते हैं तथा इनका अनुसरण भी करते हैं. एमओयू के तहत रूस में पतंजलि की आरोग्य सेवाओं का विस्तार किया जायेगा.

उन्होंने कहा, हम रूस के साथ मिलकर उम्र के प्रभाव को पलटने और लंबी जीवन प्रत्याशा पर गहन अनुसंधान करेंगे जिससे गम्भीर रोगों का मानव शरीर में आने से वर्षों पहले ही पता किया जा सकेगा.

पतंजलि भारत के आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति, योग, आयुर्वेद तथा अमूल्य धरोहरों से संबंधित ज्ञान को रूस के साथ साझा करेगी. रूस को भारत द्वारा कुशल श्रमिक तथा कुशल योगी उपलब्ध कराना भी इसमें शामिल है. एमओयू के तहत भारत के उच्च स्तरीय ब्रांड्स को रूस में तथा रूसी ब्रांड्स को भारत में बढ़ावा दिया जायेगा. हम विश्वस्तरीय पतंजलि ब्रांड को रूस लेकर जायेंगे जिससे पतंजलि के गुणवत्तायुक्त उत्पादों का लाभ रूस के नागरिकों को भी मिलेगा.

शीर्ष10 में से 5 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 72,285 करोड़ बढ़ा

मुंबई, 07 दिसंबर. पिछले सप्ताह सेंसेक्स में नगण्य साप्ताहिक तेजी के बीच बीएसई की शीर्ष 10 में से पांच कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 72,285 करोड़ रुपये बढ़ गया. टाटा समूह की सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस का एमकैप 35,910 करोड़ रुपये बढ़ा. इसी क्षेत्र की इंफोसिस के बाजार पूंजीकरण में 23,405 करोड़ रुपये और बजाज फाइनेंस में 6,720 करोड़ रुपये की तेजी रही. दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल का एमकैप 3,792 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का 2,458 करोड़ रुपये बढ़ा. शीर्ष 10 की अन्य पांच कंपनियों में गिरावट रही. विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का एमकैप सबसे अधिक 35,117 करोड़ रुपये घटा.

खुदरा महंगाई पर रहेगी निवेशकों की नजर

मुंबई, 07 दिसंबर. बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में रही गिरावट के बाद अब निवेशकों की नजर अगले सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक और खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक 09 और 10 दिसंबर को होने वाली है.

वहीं, घरेलू स्तर पर खुदरा महंगाई के नवंबर के आंकड़े 12 दिसंबर को जारी होंगे. डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में उतार-चढ़ाव का असर स्पष्ट रूप से बाजारों पर दिखेगा. औद्योगिक उत्पादन के कमजोर आंकड़ों के बाद पिछले सप्ताह शेयर बाजारों में बिकवाली हावी रही

रुपये की गिरावट से भी निवेश धारणा कमजोर हुई. हालांकि सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती से बाजार में रौनक लौट आयी, विशेषकर बैंकिंग कंपनियों में. गत सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 5.70 अंक की नगण्य बढ़त के साथ 85,712.37 अंक पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ सप्ताहांत पर 26,186.45 अंक पर बंद हुआ.

वीआईटी के उपाध्यक्ष शंकर विश्वनाथन ने रविवार को अपने भोपाल दौरे के दौरान भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के साथ शिष्टाचार मुलाकात की.

गेहूं और चीनी हुए मजबूत

मूंगफली तेल 83 रुपए प्रति क्विंटल महंगा

नई दिल्ली, 07 दिसंबर.घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव स्थिर रहे. ग्राहकी आने से गेहूं और चीनी में तेजी रही जबकि खाद्य तेलों और दालों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा.

घरेलू थोक जिंस बाजारों में सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत कमोबेश कोई साप्ताहिक बदलाव नहीं हुआ और सप्ताहांत पर यह 3,823.09 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा. गेहूं छह रुपये बढ़कर 2,844.45 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया. आटे की कीमत 13 रुपये फिसलकर 3,288.75 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी. बीते सप्ताह मूंगफली तेल 83 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ.

सरसों तेल की कीमत 44 रुपये और सूरजमुखी तेल की 13 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी. सोया तेल 11 रुपये महंगा हुआ. वनस्पति में चार रुपये और पाम ऑयल में दो रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट देखी गयी. दाल-दलहनों में सप्ताह के दौरान मसूर दाल की औसत कीमत आठ रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी.

नोएडा में अत्याधुनिक क्लब हाउस का उद्घाटन

नई दिल्ली, 7 दिसंबर. हार्ट बीट सिटी, सेक्टर-107, नोएडा में नवनिर्मित क्लब हाउस-सह-सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन माननीय मुख्य अतिथि, श्री आर. वेंकटरमणी, भारत के महान्यायवादी एवं आम्रपाली परियोजनाओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय के रिसीवर द्वारा किया गया.

इस अवसर पर न्यायालय समिति के सदस्य श्री रवि भाटिया एवं श्री डी.के. मिश्रा, एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के.पी. महादेवस्वामी, एनबीसीसी के निदेशक (वाणिज्यिक) डॉ. सुमन कुमार, हार्ट बीट सिटी के अपार्टमेंट मालिक संघ के पदाधिकारी, एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारी और सोसाइटी के निवासी उपस्थित थे. क्लब हाउस-सह-सामुदायिक केंद्र एनबीसीसी की पूरी तरह से सेवायुक्त, समुदाय-केंद्रित आवासीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. यह सुविधा हार्ट बीट सिटी के निवासियों के लिए एक स्विमिंग पूल के साथ क्लब हाउस-सह-सामुदायिक केंद्र के निर्माण के हिस्से के रूप में विकसित की गई है.

हार्ट बीट सिटी, सेक्टर-107, नोएडा में क्लब हाउस-सह-सामुदायिक केंद्र के उद्घाटन के दौरान उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

5,200 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में फैला, क्लब हाउस एक जी+2 संरचना है जो तीन लिफ्टों से सुसज्जित है. यह 350-400 व्यक्तियों की क्षमता वाले 400 वर्ग मीटर के सामुदायिक हॉल, स्क्वैश कोर्ट, क्रेच, रसोई और बहुउद्देश्यीय हॉल जैसी सुविधाओं का एक व्यापक सूट प्रदान करता है. पहली मंजिल पर योग और एरोबिक्स कमरों के साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित जिम है, जबकि दूसरी मंजिल में छह अतिथि कमरे, एक पुस्तकालय, इनडोर खेल क्षेत्र, रिसेप्शन, रसोई-सह-रेस्तरां और एक खुली छत शामिल है.

एफपीआई ने बाजार में किया 4,113 हजार करोड़ का निवेश

मुंबई, 07 दिसंबर.विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने दिसंबर के पहले सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार से 12,055 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की.

इससे पहले नवंबर में एफपीआई ने बाजार में 4,113 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था. दिसंबर में अबतक इक्विटी में एफपीआई ने 11,820 करोड़ रुपये की बिकवाली की है. इसके अलावा, उन्होंने 531 करोड़ रुपये के डेट बेचे हैं. वहीं, म्यूचुअल फंड में उन्होंने 272 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है.

531 करोड़ रुपए के डेट बेचे हैं

272 करोड़ का म्युचुअल फंड में निवेश

समाचार विशेष

जेएमएम-बीजेपी गठबंधन की बनेगी सरकार?

रांची. बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा. चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा हुआ था, जिसकी कीमत अब महागठबंधन को चुकानी पड़ रही है. दरअसल, बिहार चुनाव में एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का मौका न मिलने पर जेएमएम ने नाराज़गी जताई थी.

इसी नाराज़गी के बाद अब सीएम सोरेन अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. इसी दौरान यह अटकलें तेज हो गई हैं कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं.

साल 2024 में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे. इन चुनावों में जेएमएम और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की थी. महागठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीती थीं. इनमें 34 सीटें जेएमएम की, 16 कांग्रेस की, 4 राजद की और 2 लेफ्ट पार्टियों की थीं. अब अगर जेएमएम महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाता है, तो पूरा समीकरण बदल जाएगा. चूंकि जेएमएम के पास 34 सीटें हैं और बीजेपी के पास 20, दोनों मिलकर 54 सीटें हो जाएंगी. झारखंड में सरकार बनाने के लिए 42 सीटों की जरूरत होती है, यानी बीजेपी और जेएमएम मिलकर आराम से सरकार बना सकते हैं.

पूरा एनडीए साथ आया तो कैसा बदलेगा समीकरण

अगर जेएमएम के साथ पूरा एनडीए खेमा भी जुड़ जाता है, तो 34 जेएमएम की सीटें, 20 बीजेपी की सीटें और आजसू, एलजेपी तथा जेडीयू की एक-एक सीटें जोड़कर कुल 57 सीटें हो जाएंगी. इस तरह महागठबंधन से अलग होकर जेएमएम एनडीए का हिस्सा बन सकता है और नई सरकार बन सकती है. हालांकि, जेएमएम की ओर से अब तक ऐसी किसी संभावना को पूरी तरह नकारा गया है. वहीं इन अटकलों पर झारखंड की मंत्री और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि इन अंदाज़ों पर रोक लगनी चाहिए. यह डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है. राज्य में महागठबंधन को बहुत मज़बूत और एकतरफ़ा जनादेश मिला है.

वाइल्ड कार्ड एंट्री, रेस से बाहर हुए सारे नाम?

भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान बहुत जल्द होने की उम्मीद

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान बहुत जल्द होने की उम्मीद है. अभी के प्रेसिडेंट जे.पी. नड्डा का टर्म पहले ही पूरा हो चुका है और उनका टर्म कई बार बढ़ाया जा चुका है. हो सकता है कि यह ऐलान 15 दिसंबर 2025 से पहले हो जाए.

कहा जा रहा है कि खरमास शुरू होने से पहले यह फैसला हो जाएगा. हिंदू धर्म में मान्यता है कि खरमास के दौरान शुभ काम नहीं किए जाते, इसलिए उम्मीद है कि दस दिनों के अंदर नाम का ऐलान हो जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि हिंदुत्ववादी एजेंडे वाली पार्टी भाजपा, खरमास के दौरान इतना बड़ा फैसला नहीं लेगी.

मोदी की मीटिंग के बाद बढ़ी हलचल- 3 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस में पीएम मोदी, अमित शाह, जे.पी. नड्डा और ऑर्गनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी बी.एल. संतोष के बीच मीटिंग हुई थी. खबर है कि इस मीटिंग में नए प्रेसिडेंट, यूपी यूनिट चीफ और यूनियन कैबिनेट में फेरबदल पर चर्चा हुई. इस बारे में 1 दिसंबर को राजनाथ सिंह के घर पर धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर और दूसरे लोगों के साथ एक मीटिंग भी हुई थी. इसके बाद यह भरोसा और पक्का हो गया कि इनमें से किसी एक कैंडिडेट को अध्यक्ष का ताज पहनाया जा सकता है. हालांकि यह सब अंदाज़ा है.

चर्चा में ये नाम

अगर हम भाजपा के करीबी पत्रकारों, भाजपा की अंदरूनी पॉलिटिक्स और संघ और भाजपा में बराबर पॉपुलैरिटी जैसे फैक्टर्स को कैलकुलेट करें, तो केशव प्रसाद मौर्य और धर्मेंद्र प्रधान सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं. भूपेंद्र यादव भी रेस में हैं. शिवराज सिंह चौहान, विनोद तावड़े और सी.आर. पाटिल जैसे कई और नामों पर भी चर्चा हो रही है. मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं. 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान वे प्रदेश अध्यक्ष थे. उनके लीडरशिप में भाजपा ने यूपी में बड़ी जीत हासिल की थी.

दिल्ली में भाजपा और आप को मिल गया सबक

नई दिल्ली. दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को सबक मिल गया. चुनाव ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन दिल्ली नगर निगम, एमसीडी की 12 सीटों के नतीजों से दिल्ली के लोगों ने एक राय प्रकट की है. दिल्ली के लोगों ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है.

भाजपा पहले से जीती हुई नौ में से दो सीटों पर चुनाव हार गई है. एक सीट पर उसको आम आदमी पार्टी ने हराया तो दूसरी सीट पर कांग्रेस ने हराया. हालांकि भाजपा के नेता संतोष कर रहे हैं कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है लेकिन इससे दो सीटें हारने की भरपाई नहीं हो सकती है. लग रहा है कि महिला सम्मान योजना के पैसे नहीं दिए जाने, मोहल्ला क्लीनिक से लोगों की छंटनी, बस मार्शल को स्थायी नहीं करने और प्रदूषण के मामले ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया है.

कांग्रेस ने संगम विहार की सीट जीती है. यह मामूली बात नहीं है. यह आम आदमी पार्टी के लिए झटका है.

विशेष | इधर कांग्रेस ने छोड़ी साईकिल, उधर चार दलों ने दिया भाजपा को झटका

यूपी में क्यों मचा सियासी हड़कंप?

उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में 'दो लड़कों की जोड़ी' टूट गई है. बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा पॉलिटिकल फैसला लिया है. पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा के बीच रिश्ता खत्म हो गया है.

पार्टी का यह फैसला बुधवार को यूपी कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी के बीच हुई मीटिंग के बाद आया है. 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को सफलतापूर्वक हराया था. जिसके बाद यह माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी सपा और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन लंबे समय तक चलेगा. लेकिन अब पंचायत चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. कांग्रेस के यूपी इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा कि पार्टी आने वाले पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी.

अलग होकर क्यों लड़ना चाहती हैं पार्टियां?- हालांकि, समाजवादी पार्टी पहले ही यूपी पंचायत चुनाव लड़ने से पीछे हट चुकी है. फिर कांग्रेस ने सपा से अलग होकर पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? ये सोचनीय है. इसके अलावा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि एनडीए गठबंधन के साथी अपना दल (एस), निषाद पार्टी, आरएलडी और सुभासपा ने भी ऐलान किया है कि वे भाजपा से अलग होकर पंचायत चुनाव लड़ेंगे. इससे यह सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां पंचायत चुनाव अलग-अलग क्यों लड़ना चाहती हैं?

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का लेखा-जोखा- उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होंगे और इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है. उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का टर्म 26 मई 2026 को खत्म हो रहा है, जबकि ब्लॉक प्रमुखों का टर्म 19 जुलाई 2026 को और जिला पंचायत अध्यक्षों का टर्म 11 जुलाई 2026 को खत्म हो रहा है.

ताकत का अंदाजा लगाना चाहती है कांग्रेस!

बुधवार को सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ एक मीटिंग हुई. मीटिंग के दौरान यह तय हुआ कि कांग्रेस यूपी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी. यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस यूपी पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेगी. माना जा रहा है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक ताकत का अंदाजा लगाना चाहती है.